आरबीआई की मौद्रिक नीति क्यों मायने रखती है

लेखक - उदित मिश्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

8 अगस्त, 2019

बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में, आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 35 आधार अंकों (bps) की कटौती करने का निर्णय लिया है। रेपो दर वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। 100 बीपीएस एक पूर्ण प्रतिशत बिंदु है। आरबीआई की रेपो दर अब फरवरी से 110 आधार अंक गिर गई है। आरबीआई ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा की है।

मौद्रिक नीति क्यों मायने रखती है?

किसी भी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधि, जिसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी द्वारा मापा जाता है, चार में से एक तरीके से होती है। पहला, कोई व्यक्ति और परिवार अपने उपभोग पर पैसा खर्च करते हैं। दूसरा, सरकार अपने एजेंडे पर खर्च करती है। तीसरा, निजी क्षेत्र के व्यवसाय अपनी उत्पादक क्षमता में 'निवेश' करते हैं और चौथा, शुद्ध निर्यात (net exports)- जो सभी के द्वारा निर्यात से प्राप्त किये गये लाभ और सभी के द्वारा आयात पर किये गये खर्च के बीच का अंतर है। इनमें से किसी भी संस्था द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के अंत में यह प्रश्न निहित है कि धन की लागत क्या है?

मौद्रिक नीति अनिवार्य रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। हर देश में, केंद्रीय बैंक को पैसे की लागत तय करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अर्थव्यवस्था में 'ब्याज दर' के रूप में जाना जाता है। हालांकि, कई कारक केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल बनाते हैं और रेपो दर पर आरबीआई का निर्णय शेष अर्थव्यवस्था के

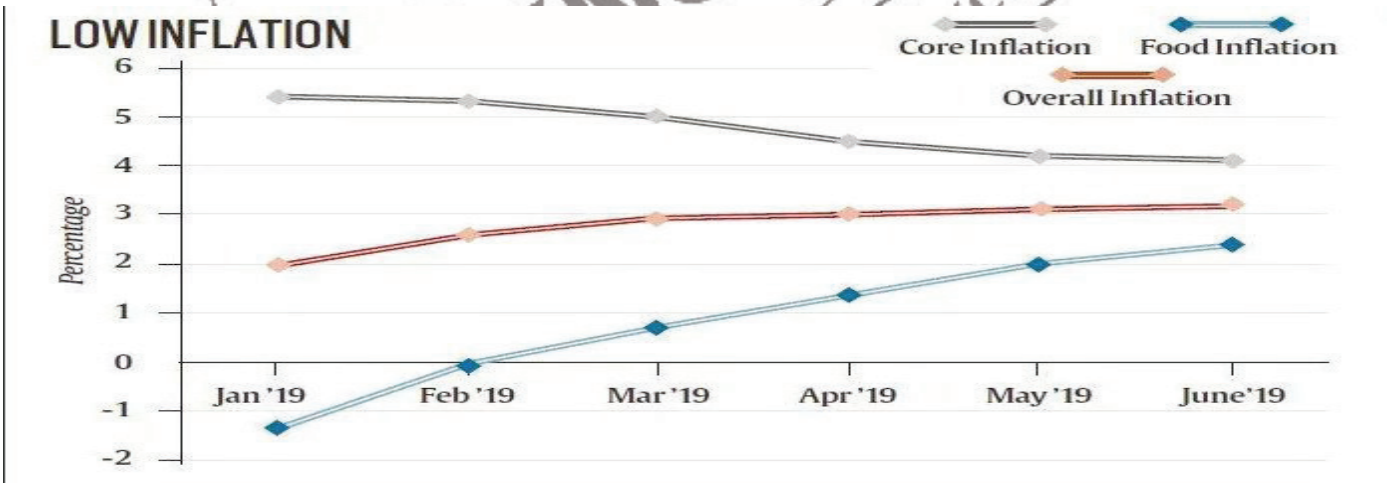

HIGH REAL INTEREST RATE

	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Repo Rate (%)	8	7.5	6.75	6.25	6	6.25
CPI Inflation (%, y-o-y)	9.4	6	4.9	4.5	3.6	3.4
Real Interest Rate (%)	-1.4	1.5	1.9	1.8	2.4	2.9

Source: National Statistics Office (NSO), CRISIL Research

लिए मानदण्ड स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में, आपकी कार या घर के लिए ईएमआई का निर्धारण आरबीआई द्वारा तय किया जाता है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो और रिवर्स रेपो अर्थव्यवस्था में आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के बीच पुनर्खरीद समझौतों का संक्षिप्त रूप हैं। रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन आदि। इस प्रकार, यदि रेपो गिरता है, तो अर्थव्यवस्था में सभी ब्याज दरों में गिरवट आती है और इसीलिए आम लोगों को आरबीआई की मौद्रिक नीति में दिलचस्पी होती है।

लेकिन फरवरी से उपभोक्ता ऋण के लिए ब्याज दर में 110 बीपीएस की कमी नहीं हुई, क्यों?

वास्तविक दुनिया में, ब्याज दर में कटौती (या वृद्धि) का 'प्रसारण' सौ फीसदी नहीं है और इसीलिए, भले ही बुधवार को आरबीआई ने 35 बीपीएस की कटौती की हो, लेकिन उपभोक्ताओं को ब्याज दर में बहुत कम कमी मिलेगी, इसकी संभावना अधिक है। यह कई कारकों के कारण है – लेकिन मुख्य रूप से, इसका संबंध संबंधित वाणिज्यिक बैंक के स्वास्थ्य से है।

पिछले कुछ वर्षों में, लगभग सभी बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने मुनाफे में कमी देखी है क्योंकि उनके पिछले कई ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में तब्दील हो गए हैं या दूसरे शब्दों में कहें, तो उन्हें चुकाया नहीं जा रहा है। इन नुकसानों के लिए बैंकों को अपने मौजूदा फंड का उपयोग करना होगा, जो कि एक नए ऋण के रूप में आम उपभोक्ताओं के पास गया होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है जो बैंकों के निर्णय को प्रभावित करता है। कम रेपो दर केवल बैंकों के नए उधार पर लागू होती है। मौजूदा फंडों की बैंकों की लागत अधिक है। बेशक, वित्त पोषण की लागत अंततः कम हो जाएगी – लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा।

मौद्रिक नीति में यह 'अंतराल' आरबीआई द्वारा किसी भी दर में कटौती की प्रभावकारिता निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर आरबीआई के इस निर्णय का पूरा प्रभाव पड़ने में 9 से 18 महीने तक का समय लग सकता है।

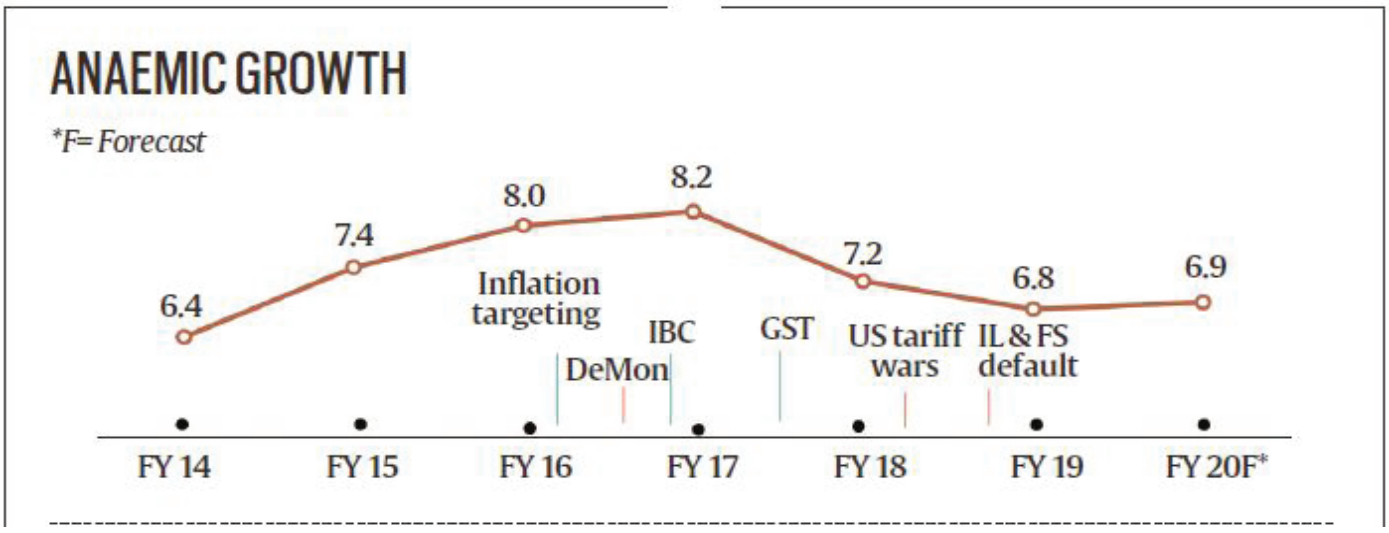

तो, RBI ब्याज दर कैसे तय करता है?

किसी भी केंद्रीय बैंक की कुछ मुख्य चिंताएँ होती हैं।

पहला, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। सोचिए कि अगर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों के बारे में कोई पूर्वानुमान न हो, तो जीवन कितना अस्त-व्यस्त हो जायेगा। ब्याज दर एक अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर करती है। आरबीआई

लगातार कीमतों और मुद्रास्फीति (जो कि कीमतों में वृद्धि की दर है) को मापता रहता है ताकि वह यह तय कर सके कि क्या उसे ब्याज दरों में वृद्धि करनी चाहिए या कमी करनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, आरबीआई ने कुछ साल पहले घोषणा की थी कि वह मुद्रास्फीति दर को 4% रखना चाहता है। इसलिए, हर बार जब खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक हो जाती है, तो आरबीआई को पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था में नकदी की अधिकता है और वस्तुओं की कमी है।

मामले को सही से सुनिश्चित करने के लिए, यह पैसे की लागत को बढ़ाता है – अर्थात्, ब्याज दर। जब ऐसा होता है, तो लोग बाजार और बैंकों से नकदी हटा लेते हैं। इस तरह, मुद्रास्फीति गिरती है। रिवर्स प्रक्रिया तब लागू होती है, जब मुद्रास्फीति 4% के नीचे होती है।

एक केंद्रीय बैंक के लिए अन्य संबंधित चिंता आर्थिक विकास का ख्याल रखना है। उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास वर्तमान में संघर्ष कर रहा है और आंशिक रूप से, मुद्रास्फीति की दर पिछले कई महीनों से 4% से नीचे है। इसलिए, आरबीआई लोगों को अधिक उपभोग करने और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज दरों में कटौती कर रहा है।

क्या दर में कटौती निवेश लाएगी?

निवेश अनिवार्य रूप से 'वास्तविक' ब्याज दर पर निर्भर करता है। वास्तविक ब्याज दर, रेपो दर और खुदरा मुद्रास्फीति के बीच का अंतर है। निवेश पर निर्णय ब्याज दर को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। यह एक निवेशक को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने की अनुमति देता है।

भारत में वास्तविक ब्याज दरें बढ़ रही हैं और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि निवेश नहीं हो रहे हैं। बुधवार को आरबीआई के कदम से वास्तविक ब्याज दर कम होगी और उम्मीद है कि अधिक निवेश आकर्षित होगा।

GS World टीम...

मौद्रिक नीति समिति (MPC, एमपीसी)

चर्चा में क्यों?

- रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी मौद्रिक समीक्षा का बुधवार को ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पालिसी यानि मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35 फीसदी या 35 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की है।
- अब रेपो रेट 5.75 फीसदी से घटकर 5.40 फीसदी हो गया है। यह 9 साल में सबसे कम है।
- वहीं, रिवर्स रेपो रेट 5.15 फीसदी हो गई है।
- रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद कर्ज सस्ता होने के साथ-साथ होम लोन (Home Loan) और ऑटो लोन की EMI कम होने की उम्मीद बढ़ गई है।
- आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.9% कर दिया है।
- जून की बैठक के बाद 7% का अनुमान जारी किया था। उस वक्त ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.2% से घटाकर 7% किया था।
- आरबीआई ने इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में रिटेल महंगाई दर 3.1% रहने की उम्मीद जताई है।
- मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में रिटेल महंगाई दर 3.5-3.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

क्या है?

- केंद्र सरकार द्वारा धारा 45ZB के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) गठित की जाती है।
- मौद्रिक नीति समिति; देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत दरों: जैसे-रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,

मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट इत्यादि का निर्धारण करती है।

- केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अनुसार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक 3 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई थी।
- रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (MPD) मौद्रिक नीति तैयार करने में MPC की सहायता करता है।

समिति का गठन

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं।
- यह समिति विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है, जो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आदि से सम्बंधित होते हैं।

मौद्रिक नीति के साधन

1. **मात्रात्मक साधन (Quantitative Instruments)**: सामान्य या अप्रत्यक्ष (कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF).
2. **गुणात्मक साधन** (Qualitative Instruments): चयनात्मक या प्रत्यक्ष (मार्जिन मनी में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव)

- यह उल्लेखनीय है कि मौद्रिक नीति के उपर्युक्त सभी उपकरण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किए जाते हैं।
- ये उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के प्रवाह को बनाए रखते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति की दर को स्थिर किया जा सके।

मौद्रिक नीति क्या है?

- मौद्रिक नीति; भारतीय रिजर्व बैंक की उस नीति को बताती है, जिसके माध्यम से देश की मौद्रिक नीति को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाये बिना देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- आरबीआई; भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति बनाने के लिए अधिकृत है।
- इसलिए मौद्रिक नीति से तात्पर्य किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण नियंत्रण उपायों से है।

इसके उद्देश्य

- चक्रवर्ती समिति के अनुसार; मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, नए मौद्रिक और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देना और पोषण करना भारत में मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।
- आरबीआई हमेशा मुद्रास्फीति की दर को कम करने या इसे एक स्थायी सीमा के भीतर रखने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर भारत सरकार देश की जीडीपी वृद्धि में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
2. आर.बी.आई. की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements-

1. Repo rate is the rate at which Reserve Bank of India lends money to commercial banks.
2. The Monetary Policy Committee (MPC) of RBI has total 6 members, including the chairman.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:1 रेपो रेट क्या है तथा आर.बी.आई. की मौद्रिक नीति में रेपो रेट की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न:2 भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में आर.बी.आई. **(Reserve Bank of India)** की भूमिका का मूल्याकंन कीजिए। (250 शब्द)

Q. 1 What is Repo Rate and Comment on the role of repo rate in the monetary Policy of RBI .

(250 Words)

Q. 2 Evaluate the role of Reserve Bank of India (RBI) in stabilising Indian economy.

(250 Words)

नोट : 7 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2 (c) होगा।

GS World
Committed To Excellence